



झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
झारखण्ड, राँची।

## प्रेस विज्ञप्ति

रांची में एक दिवसीय कार्यशाला एवं राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक  
अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करें सिविल सर्जन : के0 विद्यासागर  
रांची : झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति एवं USAID/SCALE UP RMNCH + A project के संयुक्त तत्वावधान में 10 जुलाई को होटल कैपिटल हिल, रांची में एक दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मातृत्व स्वास्थ्य पर आधारित सात नए दिशा-निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला की शुरुआत डॉ० सुमंत मिश्रा, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं के विषय प्रवेश से हुई। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से 11 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में चल रहे कार्य में प्रगति आएगी। साथ ही मातृत्व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आएगी। उन्होंने सभी सहयोगी पार्टनर एजेंसियों से इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सहयोग करने को कहा।

मैटरनल नियर मिस रिव्यू दिशा-निर्देश पर डा० देविना बाजपेई ने चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी महिला गर्भावस्था के दौरान अथवा प्रसव के बाद 42 दिन तक किसी जटिल स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित होकर मृत्यु से बच जाती है ऐसी अवस्था मैटरनल नीयर मिस कहलाएगा तथा इसकी समीक्षा करके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा।

नेशनल गाईडलाईन फॉर कैल्शियम सप्लिमेंटेशन डुरिंग प्रीगेनेसी एंड लैक्टेशन पर डा० ए० के० चौधरी, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने चर्चा करते हुए कहा कि मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भावस्था में महिलाओं को 360 कैल्शियम गोलियां एवं धातु माताओं को प्रसव उपरांत 360 कैल्शियम गोलियां प्रतिदिन सेवन करना है।

एनगेजिंग जेनरल सर्जन फॉर परफारमिंग सिजेरियन सेक्शन एण्ड मैनेजिंग ऑब्स्टेट्रिक कम्प्लिकेशन पर डॉ० ए० के० चौधरी, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने चर्चा करते हुए कहा कि सिजेरियन प्रसव एवं प्रसव के दौरान जटिलताओं के प्रबंधन हेतु जेनरल सर्जन को भी ऑन-सर्विस प्रशिक्षण देकर सहयोग करने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देश के बारे में बताया।

नेशनल गाईडलाईन फॉर डायग्नोसिस एवं मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटिज मेलिसस पर चर्चा करते हुए डा० डी० पी० तनेजा, USAID –ASSIST ने कहा कि विश्व में प्रत्येक 10 लोगों में से एक लोग डायबिटिज का शिकार है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला को इसमें फोकस किया गया है। उन्हें सारी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हैं और डायबिटिज की भी जांच करनी है। राज्य को तय करना है कि यह काम कितने जिलों में शुरू किया जाए एवं उन जिलों के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में यह कार्य करना होगा।

इसके साथ ही National Screening for HIV and Syphilis during Pregnancy , National Guidelines for screening of Hypothyroidism during Pregnancy एवं during National Guidelines for Deworming in Pregnancy पर भी चर्चा की गई।

दूसरे सत्र में जिला स्तर पर सभी जिलों में किये गए कार्य का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय कर्मियों का Rational Deployment, जिला स्तर पर पूर्व से चयनित L-1 स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त दो अन्य L-1 स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन, सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का प्रतिवेदन, सहियाओं का भुगतान से संबंधित जानकारी का ब्यौरा एवं ब्लड बैंक/ ब्लड स्टोरेज ईकाई की रिपोर्ट पर समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के प्रधान सचिव के० विद्यासागर ने सभी सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि बिना उनकी अनुमति से आगे किसी पदाधिकारी या कर्मी की प्रतिनियुक्ति नहीं करें। साथ ही ए०सी०आर० व अन्य सभी रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। बायोमैट्रिक्स सिस्टम के जरिये हाजिरी बनाने पर जोर देते हुए प्रधान सचिव ने सभी जिला को निर्देश दिया कि इस सिस्टम को सैलरी से लिंक करें। इसी हाजिरी के आधार पर वेतन निर्गत किया जाएगा। उन्होंने जुलाई माह के अंदर सभी जिलों को बायोमैट्रिक्स सिस्टम से हाजिरी बनाने का निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने जिलों में नवनिर्मित कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र को हैंडओवर करने एवं आधारभूत संसाधनों की कमियों को इंजीनियरिंग सेल से मिलकर पूरा करने का निर्देश दिया। श्री विद्यासागर ने जिले में ओपीडी में मरीजों की संख्या को बढ़ाने एवं उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश सभी सर्जन को दिया।

इस दौरान आशीष सिंहमार, अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ने सिकलसेल अनीमिया वाले मरीजों की पहचान कर उनका इलाज सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही समय पर रिपोर्टिंग करने एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया। डॉ सुमंत मिश्रा, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं साथ ही पोलियो पर आधारित प्रत्येक जिले से दो-दो बेस्ट प्रेक्टिस राज्य में भेजने का भी निर्देश सभी सिविल सर्जन को दिया।

कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के० विद्यासागर, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने की।

बैठक में डॉ० ए०के०चौधरी, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, डॉ० मंजू झा, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, डॉ० विद्या गुप्ता, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ० एम०एन०लाल, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, सभी जिलों के सिविल सर्जन, ए०सी०एम०ओ, डी०पी०एम०, राज्यस्तरीय परामर्शी/समन्वयक तथा डेवलपमेंट पार्टनर के प्रतिनिधि उपस्थित थे।



नोडल ऑफिसर  
आई० ई० सी० कोषांग